इकाई २४ दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ

इकाई की रूपरेखा

२४.० उद्देश्य

२४.१ प्रस्तावना

२४.२ इतिहास

२४.३ दक्षेस शिखर वार्ताएँ

२४.४ संगठन की अवरोधकारी समस्याएँ

२४.५ दक्षेस के लिए प्रत्याशाएँ

२४.६ सारांश

२४.७ कुछ उपयोगी पुस्तकें

२४.८ बोध प्रश्नों के उत्तर

२४.० उद्देश्य

इस इकाई में, हम दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग की प्रथम मूर्त्त अभिव्यक्ति, दक्षेस का अध्ययन करेंगे। इस इकाई के अध्ययन के बाद आप:

- एशियाई क्षेत्रीयता जिसके कारण दक्षेस का गठन हुआ, की उत्पत्ति का पता लगाने;
- दक्षेस के उद्देश्यों की पहचान करने;
- दक्षेस सम्मेलनों का संक्षिप्त विवरण देने;
- दक्षेस की अवरोधकारी समस्याओं की पहचान करने; और
- संगठन की प्रत्याशाओं का विश्लेषण करने में सक्षम हो जाएँगे।

२४.१ प्रस्तावना

क्षेत्रीयता के इतिहास में, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ (दक्षेस) एक विलक्षण परीक्षण है। राष्ट्रीय परिदृश्य अथवा महाशक्ति संयोजनों (शीत युद्ध की समाप्ति होने तक) के संदर्भ में, विश्व में कुछ समान्तर स्थितियाँ हैं। आकार, जनसंख्या, राजनीतिक तंत्रा और विकास स्थिति के संदर्भ में सात असमान राष्ट्रों-बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका से मिलकर बने इस क्षेत्रा के एक सिरे पर विश्व में (चीन के बाद) द्वितीय सर्वाधिक आबादी वाला देश भारत है तथा दूसरे सिरे पर मात्रा २००,०० की आबादी वाला मालदीव है। इसी प्रकार इसके एक तरफ भारत और पाकिस्तान जैसे विशाल सशस्त्रा बलों वाले परमाणु सत्ता सम्पन्न देश हैं तथा दूसरी तरफ भूटान और मालदीव जैसे देश हैं जिनकी संयुक्त सैनिक शक्ति नई दिल्ली अथवा कराची के पुलिस बल से अधिक नहीं होगी। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ (एशियान) में इण्डोनेशिया की स्थिति और खाड़ी सहयोग परिषद् (जी. सी. सी.) में सउदी अरब की स्थिति की इस सम्बन्ध में मात्रा सीमित तुलना की जा सकती है। महाशक्ति गठजोड़ों के सम्बन्ध में भी, शीतयुद्ध के दौरान वे असममितिक थे। भारत, यद्यपि एक गैर सोवियत गुट का राष्ट्र है, पर क्रेमलिन के साथ उसकी दोस्ती और विश्वास का साढ़े तीन दशक पुराना अभिलेख था। इसका पाकिस्तान द्वारा अधिकाधिक विरोध हुआ जो संयुक्त राज्य की भूमंडलीय रणनीति से निकट से जुड़ा हुआ था।

दक्षेस देशों की अविकसित अवस्था ऐसा क्षेत्रा है जो वस्तुत: उन देशों में समान रूप से शामिल है। सभी विकासशील देश हैं, और इनमें से चार (बांग्लादेश भूटान, मालदीव और नेपाल) विश्व बैंक की 'न्यूनतम विकसित' देशों की श्रेणी में आते हैं। जानकारी के तौर पर, दक्षेस के गठन के पीछे क्षेत्रा के आर्थिक विकास की युक्तिसंगतता थी।

२४.२ इतिहास

दक्षिण एशिया एक भलीभाँति सुपरिभाषित भौगोलिक क्षेत्रा है। ऐतिहासिक अनुभव के संदर्भ में इसमें एकरूपता है। तथापि, पर्याप्त अद्‌भुत होते हुए भी, दक्षेस इस क्षेत्रा में अपनी तरह का प्रथम परीक्षण है। यह बांग्लादेश की राजधानी ढाका में पहली बार आयोजित दक्षिण एशियाई सम्मेलन में दिसम्बर १९८५ में अस्तित्व में आया।

क्षेत्र में क्षेत्रीयवाद के लिए आरंभिक प्रयास

सामान्यत: एशिया और विशेष रूप से दक्षिण एशिया में क्षेत्रीयवाद के आंतरिक प्रयास अव्यवहारिक और अस्वाभाविक थे। सदस्यता और क्षेत्रा दोनों में अत्यधिक विसरित होने के कारण उनका कोई स्थायी महत्त्व नहीं था। उदाहरण के लिए, १९४७ और १९५५ के मध्य सात सम्मेलन बुलाए गए: एशियाई गठजोड़ सम्मेलन, नई दिल्ली, मार्च १९४७, इण्डोनेशिया पर सम्मेलन, नई दिल्ली, जनवरी १९४९, वाग्युओ सम्मेलन, वाग्युओ, फिलीपीन्स, मई १९५०; कोलम्बो योजना, यह १९५० में सिडनी और लंदन में स्वतंत्रा ब्रिटिश राष्ट्रमंडल देशों के मंत्रियों की बैठक में एक निर्णय लेने के बाद १ जुलाई १९५० को औपचारिक रूप से आरंभ किया गया; कोलम्बो शक्ति सम्मेलन, कोलम्बो, अप्रैल १९५४; अफ्रीकी-एशियाई सम्मेलन, वैनडंग, इण्डोनेशिया अप्रैल, १९५५; और शिमला सम्मेलन, शिमला, मई १९५५।

हाल ही में उपनिवेशवाद के विरोध में हुए आन्दोलनों की पृष्ठभूमि के विरुद्ध या तो उपनिवेशवाद विरोधी लोकनीतियों द्वारा अथवा भूतपूर्व उपनिवेशी मालिकों के विरुद्ध टीका-टिप्पणी करके बैठकों को अनुबोधित किया गया था जैसा कि कोलम्बो योजना में प्रतिबिम्बित था। इन बैठकों में विश्व के अनेक क्षेत्रों से देशों को शामिल किया गया था।

पश्चिमी खण्ड के प्रति झुकाव

एशियाई क्षेत्रीयता में प्रथम पीढ़ी के परीक्षण की उल्लेखनीय विशेषता थी दक्षिण एशिया का उसके उपनिवेशवाद विरोधी और साम्राज्य विरोधी वक्तृता की ओर ध्यान दिए बिना पाश्चात्य खण्ड के प्रति एकमत झुकाव। तथापि, १९५०वें दशक के मध्य के बाद, चूँकि पाकिस्तान उत्तरोत्तर संयुक्त राज्य के रणनीतिक नेटवर्क में उलझता गया, भारत और पाकिस्तान के बीच मतभेद व्यापक और गहन होते गए। उसी अवधि के दौरान, चीन-रूस के बढ़ते हुए संघर्ष ने और पेचीदा स्थिति पैदा कर दी। परिणामस्वरूप, उस समय तक भारत और पाकिस्तान के बीच बांग्लादेश की मुक्ति के मुद्‌दे पर १९७१ में तृतीय युद्ध (पहले युद्ध १९४७ और १९६५ में हुए थे) हुआ और सीमा रेखाएँ स्पष्टत: खींच दी गईं। इस पृष्ठभूमि के प्रतिकूल क्षेत्रीय सहयोग का कोई भी आह्‌वान जंगल में एक चीख के समान था।

सहकारी प्रबन्धन के विचार का पुन: प्रवर्त्तन

१९७०वें दशक के अन्त में इस विचार को पुन: बल मिला। उस समय बांग्लादेश के तत्कालीन राष्ट्रपति जियाउर्रहमान ने पहली बार सुझाव दिया कि दक्षिण एशिया के सातों राष्ट्रों को क्षेत्रा की गंभीर आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए सहकारी प्रबन्धन का आकलन करना चाहिए। यद्यपि आरंभ में इस प्रस्ताव को अधिक समुत्साह प्राप्त नहीं हुआ, देशों के नेतृत्व में परिवर्तन से यह प्रस्ताव सत्तासीन लोगों की कल्पना में समा गया। यह वह समय था जब दक्षिण एशिया में राजनीतिक नेतृत्व

नए-नए शासकों के हाथों से गुजर रहा था। भारत में, इन्दिरा गाँधी का कांग्रेस दल मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाले जनतादल द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया था; पाकिस्तान में, जुल्फिकार अली भुट्टो सैनिक शासक जिया-उल-हक द्वारा प्रतिस्थापित किये गये, और श्रीलंका में, श्रीमावो भंडारनायके जूनियस जयवर्द्धने द्वारा प्रतिस्थापित की गई। बांग्लादेश में जियाउर्रहमान ने अपनी स्थिति मजबूत की और मुजीब समर्थक बलों की तरफ से तत्काल कोई आशंका नहीं थी। ये सभी नेता संयुक्त-राज्य के समर्थक थे और अपने पूर्ववर्त्ती से भिन्न, नए परिसरों में क्षेत्रीय सम्बन्ध बनाने के लिए प्रवृत्त हुए।

दक्षेस के प्रति प्रभावी कदम

तथापि, दक्षेस गठन के प्रति प्रथम प्रभावी कदम दृढ़ता से उस समय उठाया गया जब दक्षिण एशिया का राजनीतिक परिदृश्य लगभग अपनी आरंभिक स्थिति की तरफ मुड़ गया था। इन्दिरा गाँधी ने भारत में १९८० में नाटकीय रूप से वापसी की जो अफगानिस्तान में १९७९ में सोवियत दखलन्दाजी तथा संयुक्तराज्य-पाकिस्तान के 'विशेष सम्बन्ध' की वापसी के अनुरूप थी। वास्तव में इन्दिरा गाँधी द्वारा सोवियत कार्यकारी की पुष्टि से भारत और पाकिस्तान के बीच युद्धनीतिक दरार सुस्पष्ट हो गई। जिस समय यह सब हो रहा था, जियाउर्रहमान ने मई १९८० में क्षेत्रीय सहयोग विकास के गठन के लिए गंभीर सोच की जरूरत बताते हुए छह दक्षिण एशियाई नेताओं को औपचारिक पत्रा लिखे। उल्लेखनीय बात यह थी कि इस अपील को स्वीकारात्मक लेकिन शिथिल प्रतिक्रिया प्राप्त हुई।

राजनीतिक प्रश्नों का प्रत्यक्ष हवाला दिए बिना तथा संवेदनात्मक क्षेत्रीय पहलुओं का स्पर्श किए बिना, नेताओं ने पारस्परिक आर्थिक सहयोग के क्षेत्रों की तलाश करना बेहतर समझा। यह वह समय था जब उत्तर-दक्षिण वार्त्तालाप व्यावहारिक तौर पर विफल हो गया था और दक्षिण-एशिया सहयोग के तहत विकासशील देशों के बीच आर्थिक सहयोग का नारा बुलन्द होता गया। भूमण्डलीय मंदी से विश्व अर्थव्यवस्था उत्तरोत्तर क्षीण होने लगी। तेल-निर्यातक विकासशील विश्व जिससे दक्षिण एशिया सम्बन्धित था, सर्वाधिक प्रभावित हुआ। १९७०वें दशक के मध्य तक वास्तविक वृद्धि दर लगभग दो प्रतिशत की निम्नदर पर पहुँच गई थी। १९७९-८० के 'द्वितीय तेल आघात' ने हालात को और बिगाड़ दिया। १९८० में सभी दक्षिण एशियाई देशों के व्यापार रिकार्ड का संतुलन बहुत ही शोचनीय स्थिति में पहुँच गया था। इस पृष्ठभूमि के विपरीत; विकासात्मक कार्यसूची में विशेषत: क्षेत्रीय सहयोग और सामान्यत: दक्षिण-दक्षिण सहयोग के औचित्य को उच्च प्राथमिकता मिली। दक्षेस का गठन मात्रा एक सामाजिक मामला था।

सहयोग के क्षेत्रों का पता लगाने के लिए सचिव स्तर पर कई बैठकें आयोजित की गई। इन बैठकों की मुख्य बातें यह थीं कि सभी ने अपनी क्षेत्रीय बैठकों में किसी भी प्रकार के 'द्विपक्षीय अथवा विवादग्रस्त' मुद्दों को न उठाने का फैसला किया और इस बात पर भी सहमत हुए कि जो भी निर्णय होगा, एक मत के आधार पर लिया जाएगा। ध्यान देने योग्य बात यह थी कि पहला निर्णय भारत के आग्रह पर तथा दूसरा निर्णय भारत और पाकिस्तान दोनों के आग्रह पर लिया गया था; अन्य देशों को उनके बारे में चिन्ता करने का कोई विशेष कारण नहीं था। इन दो शर्तों के द्वारा दक्षेस की मौलिक कार्यवाही जारी है। इसके प्रतिकूल, ऐसे द्विपक्षीय मुद्दों को शामिल करने की उनकी प्राथमिकता होगी जिनसे उन्हें भारत-महामूर्ति और अक्सर जिसका 'बड़े भाई' के रूप में हवाला दिया गया, के साथ वार्त्ता करने का विश्वास पैदा होगा। एक प्रकार से, भारत के लिए यह एक प्रमुख राजनीतिक उपलब्धि थी।

दक्षेस का सूत्रपात

अगस्त १९८३ में, गतिशील प्रक्रिया को एक राजनीतिक प्रोत्साहन मिला। नई दिल्ली में, विदेश मंत्रियों के प्रथम सम्मेलन में, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग उद्घोषणा को अपनाया गया। इसके अनुक्रम में, दक्षेस में संगठनात्मक ढाँचे को अन्तिम रूप दे दिया गया।

तदोपरान्त, प्रथम शिखर बैठक दिसम्बर १९८५ में ढाका में सम्पन्न हुई और दक्षेस का औपचारिक रूप से सूत्रापात किया गया। नेताओं ने मंत्रिापरिषद् और सचिवालय के पक्ष में निर्णय लिया और संगठन में उनकी स्थायी वचनबद्धता प्रमाणित की। फरवरी १९८७ में, दक्षेस सविचालय एक महासचिव और चार निदेशकों के साथ आरंभ हुआ। तदोपरान्त, दक्षेस मंत्रिपरिषद् का गठन किया गया जो सम्बन्धित सदस्य राष्ट्रों के विदेश मंत्रियों से मिलकर बना था।

संगठनात्मक ढाँचा

१९८३ में विदेश मंत्रियों की नई दिल्ली बैठक के क्रम में, दक्षेस के संगठनात्मक ढाँचे ने एक सुस्पष्ट स्वरूप और आकृति प्राप्त की। यह चार-स्तरीय ढाँचे के रूप में विकसित हुआ। सबसे निचले स्तर पर विशेषज्ञों और कर्मचारियों की तकनीकी समितियाँ थीं जिन्हें कार्यवाई हेतु कार्यक्रम तैयार करने थे तथा सम्मेलनों और कार्यशालाओं का आयोजन करना था। इसके बाद विदेश मंत्रियों की स्थायी समिति थी जिसे तकनीकी समितियों, जिनकी वर्ष में कम से कम एक बार बैठक होनी थी, की सिफारिशों की समीक्षा करनी थी। इसके ऊपर विदेश मंत्रियों का सम्मेलन था जिसे स्थायी समिति की सिफारिशों को राजनीतिक अनुमोदन स्वीकृत करने के लिए एक वर्ष में कम से कम एक बार आयोजित होना था। सबसे ऊपर दक्षेस को राजनीतिक महत्त्व देने के लिए वार्षिक तौर पर शिखर बैठक आयोजित की जानी थी।

बोध प्रश्न १

नोट : i) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए रिक्त स्थान का प्रयोग करें।

ii) अपने उत्तर इकाई-अंत में दिए गए उत्तरों से मिलाएँ।

१) दक्षेस के गठन में भूमिका अदा करने वाले रूप में तीन घटकों की पहचान करें।

.....

.....

.....

.....

.....

२) दक्षेस के संगठनात्मक ढाँचे के चार स्तर कौन से हैं?

.....

.....

.....

.....

.....

२४.३ दक्षेस शिखर वार्ताएँ

अब तक बारह शिखर वार्ताएँ हो चुकी हैं – ढाका (१९८५), बंगलौर (१९८६), काठमांडु (१९८७), इस्लामाबाद (१९८८), माले (१९९०), कोलम्बो (१९९१), ढाका (१९९३), नई दिल्ली (१९९५), माले (१९९७), कोलम्बो (१९९८), काठमांडु (२००२) और इस्लामाबाद (२००४)। तथापि गत समय में,

कई शिखर वार्ताएँ सदस्य देशों की घरेलू अथवा द्विपक्षीय समस्याओं के कारण स्थगित हो गई है अथवा बिल्कुल आयोजित नहीं हुई हैं।

दक्षेस का बैठकों, सम्मेलनों, अध्ययनों और रिपोर्टों जिन्हें इसने प्रायोजित किया है, का एक समुचित प्रभावशाली रिकार्ड है। दक्षेस सचिवालय द्वारा समय-समय पर जारी क्रियाकलापों के कलेण्डर से विविध विकासोन्मुख क्षेत्रों से सम्बन्धित क्रियाकलापों की एक बड़ी संख्या का पता चलता है जैसे कृषि, पशुपालन, बागवानी, स्वास्थ्य और स्वच्छता, जंगलात, जनसंख्या, मौसम विज्ञान, डाक सेवा, औषधि व्यापार और उसका दुरुपयोग, समेकित ग्रामीण विकास, प्रौद्योगिकी अन्तरण, खेल, परिवहन, दूरसंचार, महिला विकास, व्यापार और वाणिज्य तथा अन्य।

दक्षेस के क्रियाकलाप मात्रा विकासोन्मुख मुद्दों तक ही सीमित नहीं हैं। आतंकवाद जैसा मुद्दा जो अनेक वर्षों से भारत-पाक सम्बन्धों में आग लगा रहा है और जिसके गंभीर राजनीतिक परिणाम हैं, उसने भी आरंभ में दक्षेस का ध्यान आकर्षित किया। इस प्रश्न पर दक्षेस देशों के बीच गहरे बैठे मतभेदों के बावजूद उन्होंने आतंकवाद के विरुद्ध एक समागम अपनाया।

इसकी प्रमुख बात उन अपराधों की पहचान करना था जिन्हें आतंक के रूप में माना जाएगा और प्रत्यर्पण के प्रयोजनार्थ उन्हें राजनीतिक अपराध अथवा राजनीतिक गतिविधियों से प्रेरित अपराध नहीं माना जाएगा। समागम में द्विपक्षीय प्रत्यर्पण सन्धियों के हस्ताक्षर के माध्यम से आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई का प्रावधान है, तथापि, इन पर अभी तक हस्ताक्षर नहीं हुए हैं। इस समागम को लागू नहीं किया गया है क्योंकि बांग्लादेश और पाकिस्तान ने उसका समर्थन नहीं किया है। इसका कारण यह है कि उनके पास आतंकवादियों के विरुद्ध सक्षम घरेलू कानून नहीं है। तथापि, २००४ की इस्लामाबाद शिखर वार्ता में इस समागम को एक नई दिशा प्रदान की गई।

प्रथम दक्षेस शिखर वार्ता दिसम्बर १९८५ में ढाका में आयोजित की गई थी। इस बैठक में, दक्षेस का औपचारिक सूत्रापात किया गया था। यह शिखर वार्ता विशेषतया दो प्रकार से महत्त्वपूर्ण थी। प्रथमत: इसमें 'बलों को प्रयोग में न लाना' और ''सभी विवादग्रस्त मुद्दों का शान्तिपूर्ण समाधान' (आमुख और अनुच्छेद II) अभिव्यक्तियों का प्रयोग किया गया था। ध्यान दिया जाना चाहिए कि इसी प्रकार की अभिव्यक्तियाँ बांग्लादेश द्वारा तैयार किए गए मूल कार्यकारी दस्तावेज (१९८०) में प्रयुक्त की गई थी, परन्तु विदेश मंत्रियों की प्रथम बैठक में पाकिस्तान के प्रारक्षण के कारण उन्हें हटा दिया गया था। पाकिस्तान का 'कोई युद्ध नहीं' समझौता प्रस्ताव सितम्बर १९८१ में बाद में भारत आया। इस प्रकार, दक्षेस दस्तावेज में इन अभिव्यक्तियों के प्रयोग से वस्तुत: 'कोई युद्ध नहीं' प्रस्ताव व्यर्थ हो गया। दूसरे, शिखर वार्ता में मंत्रिापरिषद और पाकिस्तान के पक्ष में निर्णय लिया गया जिससे दक्षेस को स्थायित्व प्रदान किया जा सके।

नवम्बर १९८६ में बंगलौर में आयोजित द्वितीय दक्षेस शिखर वार्ता में, नेताओं ने आतंकवाद को दबाने के लिए एक क्षेत्रीय समागम किया। एकक्षेत्रीय खाद्य सुरक्षा आरक्षी निधि की स्थापना के लिए सहमति दी गई और प्राकृतिक आपदा के कारणों और परिणामों तथा पर्यावरण प्रारक्षण पर अध्ययन के लिए निर्णय लिया गया। सदस्यता के लिए अफगान प्रार्थनापत्रा के जवाब में शिखर वार्ता में सदस्यता के लिए मानदण्ड तैयार करने के लिए स्थायी समिति को दिशा निर्देश दिया गया। (नए सदस्यों के प्रवेश पर दक्षेस चार्टर खामोश है।)

तृतीय दक्षेस शिखर वार्त्ता नवम्बर १९८७ में काठमांडु में आयोजित की गई। शिखर वार्ता में आतंकवाद के दमन पर दक्षेस क्षेत्रीय समागम पर हस्ताक्षर किए गए जो २२ अगस्त १९८८ से लागू हुआ।

चतुर्थ दक्षेस शिखर वार्ता १९८८ में इस्लामाबाद में सम्पन्न हुई। इस शिखर वार्ता में, एक समेकित विकास योजना तैयार की गई जिसे ''दक्षेस २००० – एक बुनियादी आवश्यकता संदर्श'' का नाम दिया गया। इस योजना में एक क्षेत्रीय संदर्श कार्यक्रम निर्धारित किया गया जिसका विशिष्ट लक्ष्य मौलिक क्षेत्रों जैसे खाद्य, कपड़ा, आश्रय, शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य, सुरक्षा, जनसंख्या नियोजन और पर्यावरण सुरक्षा को वर्ष २००० तक प्राप्त करना था।

पंचम दक्षेस शिखर वार्त्ता नवम्बर १९९० में माले में आयोजित की गई। इस शिखर वार्त्ता में, नेताओं ने अक्षम और कन्या शिशु के कल्याण, क्षेत्रा में औषधि दुरुपयोग की आशंका से प्रभावी ढंग से निपटने तथा अवैध व्यापार के दमन के लिए नार्कोटिक औषधियों और मनस्तापी पदार्थों पर समागम, सांसदों और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की विद्यमान श्रेणियों के अलावा राष्ट्रीय अकादमी संस्थानों के प्रमुखों, उनके जीवनसाथियों (पति/पत्नी) और निर्भर बच्चों को शामिल करने के लिए वीसामुक्त यात्राा सुविधा के विस्तार और सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण आर्थिक सहयोग के मूल क्षेत्रों के विस्तार के लिए आह्वान किया। यह निर्णय लिया गया था कि फरवरी १९९१ के अन्त तक व्यापार, विनिर्माण और सेवाओं के विवादग्रस्त मुद्दों पर क्षेत्रीय अध्ययन पूरा हो जाना चाहिए। यह विशेष रूप से इसलिए महत्त्वपूर्ण था क्योंकि प्रत्येक इस तथ्य से सहमत था कि समाजवादी अर्थव्यवस्था के पतन से भूमण्डलीय अर्थव्यवस्था के सम्मुख उपस्थित चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए, उत्पादन, उपयोग और व्यापार के नये प्रतिमान की और ध्यान देना होगा और जितना जल्दी यह संभव होगा उतना ही अधिक दक्षिण एशिया के लिए बेहतर होगा।

कोलम्बो में षष्ठम् दक्षेस शिखर वार्ता मूलत: नवम्बर १९९१ में आयोजित होनी थी। परन्तु भूटान के राजा की अपनी विकट घरेलू समस्याओं के कारण तथा अन्तिम क्षण में उनके शिखर वार्ता में शामिल न होने के निर्णय के कारण, बैठक को स्थगित करना पड़ा। यह अपरिहार्य था क्योंकि भारत और नेपाल दोनों का आग्रह था कि चूँकि भूटान के राजा शामिल नहीं हो रहे थे अत: वे भी शामिल नहीं होंगे। उन्होंने उत्कट रूप से महसूस किया कि शिखर वार्ता के एक भी सदस्य की अनुपस्थिति में, यदि उसे आयोजित किया भी गया तो यह दक्षेस की सामूहिक भावना के प्रतिकूल होगा।

तत्पश्चात् शिखर वार्ता २१ दिसम्बर १९९१ को आयोजित हुई। कोलम्बो उद्घोषणा में जिसे शिखर वार्ता में अपनाया गया था, अधिकांश मुद्दे, दक्षेस के पूर्व वर्षों से चली आ रही कार्यसूची का अंश थे। आतंकवादी क्रियाकलापों के दिक्परिवर्तन की आवश्यकता, छोटे राज्यों की सुरक्षा कायम करने के लिए अन्तरराष्ट्रीय आम राय प्राप्त करने के लिए मालदीवी पहल, दक्षिण एशिया में नार्को-आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए प्रभावी कदम उठाने का आह्वान, भूमण्डलीय और क्षेत्रीय पर्यावरण सम्बन्धी मुद्दों पर सामूहिक दृष्टिकोण अपनाने की दलील इस श्रेणी में आते थे। शिखर वार्ता के नेता इस पर भी सहमत हुए कि व्यापार, विनिर्माण और सेवाओं के क्षेत्रों में क्षेत्रीय सहयोग के लिए प्रत्याशाओं का अध्ययन करने के लिए पहले ही गठित अन्तर-सरकारी ग्रुप को १९९७ तक एक दक्षेस अधिमान्य व्यापार प्रबन्धन की स्थापना के लिए श्रीलंका के प्रस्ताव की भी जाँच करनी चाहिए।

कोलम्बो शिखर वार्ता में लिए गए सभी निर्णयों में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण समझौता यह था कि दक्षेस विदेश सचिवों का विशेष सत्रा संगठन के कार्यकारी मानदण्डों के रक्षा उपायों के अध्ययन के लिए १९९२ में कोलम्बो में आयोजित किया जाना चाहिए। इस अध्ययन में प्रस्तावों की लम्बी सूची को शामिल किया गया जिनमें वे प्रस्ताव भी शामिल थे जो दक्षेस चार्टर में परिवर्तन के लिए अभिकल्पित थे। इसमें अन्य क्षेत्रीय संगठनों जैसे एशियान और यूरोपीयन संघ के साथ उपयुक्त 'बाहरी गठबंधनों' की स्थापना के मुद्दे पर भी विचार किया जा सका।

सप्तम दक्षेस शिखर वार्ता ढाका में अप्रैल १९९३ में सम्पन्न हुई। इस शिखर वार्ता में, दक्षेस अधिमान्य व्यापार प्रबन्धन पर हस्ताक्षर किए गए। करार में सदस्य देशों को टैरिफ, पैरा टैरिफ, नॉन-टैरिफ तथा प्रत्यक्ष व्यापार क्रियाकलापों के माध्यम से उनके मध्य चरणबद्ध मुक्त व्यापार मुहैया कराने की कल्पना की गई थी।

नई दिल्ली में १९९५ में सम्पन्न अष्टम् दक्षेस शिखर वार्ता में दक्षेस अधिमान्य व्यापार प्रबंधन (SAPTA) को औपचारिक रूप से आरंभ किया गया।

माले में १९९७ में आयोजित नवम् दक्षेस शिखर वार्त्ता में प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्तियों के दक्षेस ग्रुप की स्थापना की गई थी। ग्रुप ने एक दक्षेस सर्वनिष्ठ बाज़ार के सृजन और विशाल पैमाने पर आर्थिक नीति समन्वयन लागू करके दक्षेस आर्थिक दर्शन का गठन निर्धारित किया।

दक्षेस अधिमान्य व्यापार प्रबन्धन की बातचीत से हुई प्रगति से प्रोत्साहित होकर, १९९८ में कोलम्बो में दशम् दक्षेस शिखर वार्ता बैठक में, दक्षेस नेताओं ने दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र(SAFTA) पर संधि का मसौदा तैयार करने के लिए विशेषज्ञों की समिति गठित करने का निर्णय लिया। संधि में विधिगत रूप से दक्षेस देशों के मध्य व्यापार को मुक्त करने के लिए बाध्यकारी अनुसूचियाँ निर्धारित करने तथा क्षेत्रा में मुक्त व्यापार क्षेत्रा की प्राप्ति के लिए एक पूर्वानुमेय और पारदर्शी समय पथ मुहैया करने की उम्मीद की गई थी।

काठमाण्डु में एकादश दक्षेस शिखर वार्ता मूलत: नवम्बर १९७९ में आयोजित की जानी थी परन्तु इसे १२ अक्टूबर १९९९ को पाकिस्तान में सैनिक टकराव के कारण स्थगित करना पड़ा। संयोगवश, शिखर वार्ता जनवरी २००२ में आयोजित हुई। इस शिखर वार्त्ता को प्रमुख अंश क्षेत्रा के आरपार अनैतिक प्रयोजनार्थ महिला शिशु और महिलाओं के अवैध व्यापार पर रोक लगाने के लिए एक समागम पर हस्ताक्षर करना था। तथापि, शिखर वार्ता कराने में विलम्ब का यह अर्थ नहीं था कि दक्षेस निष्क्रिय हो गया था। दक्षिण एशियाई विकास निधि (SADF) के शासकीय बोर्ड की छठवीं बैठक २२ जुलाई २००० को मालदीव में आयोजित की गई थी जिसमें निधि के क्रियाकलापों की समीक्षा की गई थी और पेशागत आधार पर निधि को नियोजित करने के लिए प्रस्तावों पर चर्चा की गई थी। दक्षेस संकाय ने शिक्षा के सभी स्तरों पर मुक्त और दूरस्थ शिक्षा के प्रयोग को प्रोन्नत करने के लिए दक्षेस क्षेत्रा में सहयोग के लिए प्रस्तावों की जाँच की। इस वर्ष के दौरान व्यक्ति से व्यक्ति के मध्य सभी प्रकार का बढ़ता सम्पर्क एक उल्लेखनीय विकास था। भूमण्डलीय, वित्तीय और आर्थिक मुद्दों पर दक्षेस शोधकर्ता नेटवर्क की तृतीय बैठक ३१ अक्टूबर २००० को दक्षेस सचिवालय में सम्पन्न हुई। दक्षेस श्रवण दर्शन विनिमय समिति की उन्नीसवीं बैठक १९-२० को ढाका में आयोजित हुई।

१३-१५ नवम्बर २००० से एक विशेष दक्षेस वरिष्ठ कर्मचारी बैठक कोलम्बो में आयोजित हुई। बैठक में तकनीकी समिति की बैठकें, दक्षिण एशियाई अधिमान्य व्यापार प्रबन्धन (SAPTA) और दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्रा (SAFTA) की विशेषज्ञ स्तर पर बैठकें कराने के लिए कलेण्डर को अन्तिम रूप दिया गया। दक्षेस समेकित कार्य योजना (SIPA) के कार्यान्वयन के लिए दक्षेस तकनीकी समितियाँ प्रथम साधन हैं। 'दक्षिण एशिया में स्थायी विकास और ग्रामीण उन्मूलन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा के वित्तपोषण पर क्षेत्रीय बैठक' संयुक्त रूप से विश्व ऊर्जा परिषद् के साथ १२-१४ जून २००२ को कोलम्बो में आयोजित की गई। एक दक्षिण एशियाई कारोबारी नेताओं की शिखर वार्त्ता १८-१९ अगस्त २००० को बंगलौर में सम्पन्न हुई जो द फेडरेशन ऑफ कर्नाटक चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री, द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री(FICCI) तथा दक्षेस चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री की संयुक्त पहल के रूप में थी। दक्षेस विधि कान्फ्रेंस, एक मान्यताप्राप्त क्षेत्रीय उच्चतम दक्षेस निकाय, ने २२-२४ सितम्बर, २००० से नेपाल में अपना आठवाँ वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया। दक्षिण क्षेत्रा में स्वास्थ्य सेक्टर में सुधार के लिए अपने कुछ प्रयासों के रूप में, दक्षेस ने २-३ अगस्त २००० को विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

द्वादश दक्षेस शिखर वार्ता ४-६ जनवरी २००४ से इस्लामाबाद में आयोजित हुई। इस शिखर वार्ता की कई देशों द्वारा जय-जयकार की गई क्योंकि भारत और पाकिस्तान के दो नेता भारी सौजन्यता से एक-दूसरे से मिले जिससे द्विपक्षीय सम्बन्धों में सुधार और दक्षेस प्रक्रिया के विकास दोनों का अनुमान लगाया गया। इस शिखर वार्ता ने क्षेत्रीय सहयोग के कई क्षेत्रों में दूरगामी सिफारिशें की। प्रथमत:, इसमें दक्षेस सामाजिक चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए जिसमें गरीबी उन्मूलन, जनसंख्या नियंत्राण, महिलाओं को शक्तिसम्पन्न करना, युवकों की लामबंदी, मानव संसाधन विकास, स्वास्थ्य और पोषण की प्रोन्नति जैसे मुद्दे शामिल किए गए हैं। ये सभी संभवतया दक्षिण एशिया के लाखों प्राणियों की जीविका पर दूरगामी प्रभाव छोड़ेंगे। दूसरे, आतंकवाद के मुकाबले के लिए १९८७ में हस्ताक्षरित क्षेत्रीय समागम पर वचनबद्धता की पुन: पुष्टि करते समय, उन्होंने आतंकवाद के वित्त पोषण से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए इस समागम के एक अतिरिक्त समझौते पर हस्ताक्षर किए।

तीसरे, सदस्यों ने दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्रा(SAFTA) के प्रारूप करार पर हस्ताक्षर किए और उसे जनवरी २००६ तक लागू किया। और अन्ततः, शान्ति, विकास, ग़रीबी उन्मूलन और क्षेत्राीय सहयोग के अन्य क्षेत्राों में असाधारण व्यष्टियों और संगठनों को सम्मानित और प्रोत्साहित करने के लिए दक्षेस पंचाट संस्थापित किया गया।

बोध प्रश्न २

नोट : i) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए रिक्त स्थान का प्रयोग करें।

ii) अपने उत्तर इकाई-अंत में दिए गए उत्तरों से मिलाएँ।

१) ढाका में आयोजित प्रथम दक्षेस शिखर वार्ता की क्या उपलब्धियाँ थीं?

.....

.....

.....

.....

.....

२४.४ संगठन की अवरोधकारी समस्याएँ

उपरोक्त चर्चा से ऐसा प्रतीत होगा कि दक्षेस के उद्देश्य विकासोन्मुख रखे गए हैं। जब दक्षेस का एक क्षेत्राीय संगठन के रूप में उदय हुआ था, उस समय क्षेत्रा को पारस्परिक सहयोग, सामूहिक आत्म विश्वास और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का फलता-फूलता उदाहरण बनाने के लिए इसकी संकल्पना स्पष्ट थी। आर्थिक विकास की गति को बढ़ाना, लोक कल्याण की प्रोन्नति और उनके जीवन स्तर में सुधार केन्द्रीय उद्देश्य रहे हैं। आर्थिक सहयोग को प्रोत्साहित करने और सभी विवादग्रस्त और द्विपक्षीय मुद्दों से अलग रहने के लिए सचेतन प्रयास किए गए हैं। परन्तु जब हम इसे विकासोन्मुख महत्त्वाकांक्षाओं वाला कहकर प्रशंसनीय मानते हैं, तब यह अनिश्चित होता है कि संगठन का उस समय क्या होगा जब इसके सम्मुख ऊपर से नीचे तक और अधिक ऐसे राजनीतिक सवाल उठ खड़े होंगे जिनके कारण दशकों से इस क्षेत्रा में अन्तर-राज्यीय संबंध बिगड़े हैं। यह क्षेत्रा विरोधाभासों से भरा पड़ा है जो दो मुख्य वर्गों में आते हैं: विविध सुरक्षा हित और क्षेत्रा का भारत-मूलक स्वरूप।

संरचनात्मक विरोध

दक्षेस एक संरचनात्मक विरोध से ग्रस्त है। भारत का असमानुपाती विशाल आकार अपने पड़ौसी की समान भागीदारों के रूप में भागेदारी जो किसी भी सहकारी प्रयास में निर्णायक है, का विरोध करता है। भारत इस क्षेत्रा की भूमि के ७२ प्रतिशत, इसकी जनसंख्या के ७७ प्रतिशत और सकल घरेलू उत्पाद के ७८ प्रतिशत के लिए उत्तरदायी है। इसकी सशस्त्रा सेना इस क्षेत्रा के सम्पूर्ण सशस्त्रा बल का ५० प्रतिशत बनती है और यदि पाकिस्तान को छोड़ दिया जाए (जो लगभग २५ प्रतिशत के लिए उत्तरदायी है), भारत और शेष पाँच को एक साथ मिलाकर रखने पर अनुपात नौ और एक होगा।

विरोधाभासी सुरक्षा अवबोधन

सामाजिक-ऐतिहासिक कारणों से उद्भूत अविश्वासों से जुड़ी हुई इस सकल विसंगति से विरोधमूलक सुरक्षा दृष्टिकोणों में वृद्धि होती है। पाकिस्तान को छोड़कर, भारत को इस क्षेत्रा में किसी अन्य देश से कोई खतरा नहीं है। इसकी सुरक्षा को ख़तरा वस्तुतः क्षेत्रा से बाहर है और इस संदर्भ

में पाकिस्तान की चीन के साथ सम्बन्धों की सुसंगता सामने आती है। इस क्षेत्रा में दूसरों के लिए (भूटान जिसकी विदेश नीति कमोबेश भारत द्वारा दिशा निर्देशित है और मालदीव जो भारत की सहायता के बिना अपनी रक्षा के लिए स्वयं बहुत छोटा है जैसा कि १९८८ की सैनिक भिड़न्त से प्रकट हुआ, को छोड़कर) भारत स्वयं एक ख़तरा है जिसका केवल क्षेत्रा के बाहर गठजोड़ों से मुकाबला किया जा सकता है। क्षेत्रा के अवबोधन में यह द्विभाजन और तदनुरूप सुरक्षा सिद्धांत दक्षेस के लिए अच्छी भविष्यवाणी नहीं कर सकते। यह देखना महत्त्वपूर्ण है कि तृतीय विश्व की एकता, गत समय में ऊपर से नीचे तक लगभग सभी पूर्वी-पाश्चात्य सीमाओं जैसे अफगानिस्तान और कम्पूचिया, सीमाओं पर नया अन्तरराष्ट्रीय आर्थिक प्रबन्ध आदि, के प्रति वाग्मितापूर्ण वचनबद्धता को छोड़ने पर स्थिति भारत बनाम शेष क्षेत्रा के लिए अभिमुख है।

विविध राजनीतिक संस्कृति समस्या

क्षेत्रा की विविध राजनीतिक संस्कृति भी सहयोग के लिए अभिप्रेरक नहीं है। इस क्षेत्रा में प्रचलित शासकीय तंत्रों के दृष्टिकोण से चार प्रकार के प्रजातंत्रा (बांग्लादेश, भारत, नेपाल और श्रीलंका), एक सैनिक तानाशाही (पाकिस्तान), एक राजतंत्रा (भूटान) और एक दलीय राष्ट्रपति तंत्रा (मालदीव) हैं। राष्ट्र-धर्म सम्बन्धों के सवाल पर, भारत उसके हिन्दू बहुल होने और अभी तक अभूतपूर्व हिन्दू सेना का साक्षी होने के बावजूद धर्मनिरपेक्षता के लिए कायम है जबकि शेष छह स्वयं की इस प्रकार की घोषणा से बचना चाहते हैं। बांग्लादेश, मालदीव और पाकिस्तान में इस्लामी, भूटान और श्रीलंका में बौद्ध तथा नेपाल में हिन्दू हैं। भूमण्डलीय व्यवस्था के साथ जिसने गत समय में काफी बदलाव महसूस किए हैं, संरचनात्मक तालमेल के सम्बन्ध में, व्यापक तौर पर केवल दो वर्ग थे। प्रथम के पास जिसमें भारत को सम्मिलित किया गया था, एक पर्याप्त शक्तिशाली पूँजीवादी वर्ग था जिसने वर्ष दर वर्ष पूँजीवादी और समाजवादी तन्त्रा दोनों में आधिपत्य कायम किया था यद्यपि यह दोनों से स्वतंत्रा था। दूसरे वर्ग के पूँजीवादी तंत्रा और मध्य वर्ग विश्व के साथ गहरे संरचनात्मक सम्बन्ध थे, वहाँ व्यापक पैमाने पर चीनी मध्यस्थता (Comprador) थी। बांग्लादेश, मालदीव, पाकिस्तान और श्रीलंका इस वर्ग से जुड़े हुए थे। भूटान की अर्थव्यवस्था व्यापक तौर पर भारत-मूलक है। नेपाल की अर्थव्यवस्था भारत-मूलक तथा विकसित बाज़ार अर्थव्यवस्थाभिमुखी है।

इन व्यवस्थागत विविधताओं से विविध राष्ट्र निर्माण रणनीतियों का सूत्रापात हुआ जो एक-दूसरे के अभिलाभ में योगदान देने की बजाए एक-दूसरे के खर्चे पर फूल-फल रही थीं। उदाहरणार्थ, क्षेत्रा की प्रजातीय व्यवस्था इतनी जटिल है कि एक राष्ट्र द्वारा अपने अन्तर-प्रजातीय सम्बन्धों से निपटने में ज़रा-सी अकुशलता पड़ौसी राज्य को प्रभावित करता है। इस संदर्भ में, भारत ने एक से अधिक तरीकों से आघात सहा है। क्षेत्रा के मूल में अवस्थित होने के कारण, इसकी सीमाएँ दक्षेस के लगभग सभी देशों की सीमाओं को स्पर्श करती हैं जबकि किन्हीं अन्य दो सदस्यों की उभयनिष्ठ सीमा नहीं है। भारत, बहुप्रजातीय, बहुभाषीय और बहुधार्मिक समाज के रूप में, क्षेत्रा के अन्य देशों के साथ अपने प्रजातीय, भाषाई अथवा धार्मिक भाईचारे के कुछ सम्बन्ध बनाए रखता है जबकि किन्हीं अन्य दो देशों की अन्यान्य राष्ट्रीय प्रजातीय जनसंख्या नहीं है जिस पर भूटान और श्रीलंका के उल्लेखनीय अपवाद को छोड़कर, किसी भी निष्कर्ष के लिए पर्याप्त रूप से विचार किया जा सके। भारत इस समस्या की भारत-मूलकता से क्षेत्रा के प्रजातीय संघर्ष में फँस जाता है जिससे यह शायद ही मुक्त होता है। तथापि, इसी के साथ, भारत के पास सामरिक रियायतों का लाभ उठाने के लिए एक अक्खड़ पड़ौसी को दिग्भ्रमित करने का अवसर रहता है। यदि सिंहल-तमिल प्रजातीय संघर्ष में भारत की भूमिका न होती तो श्रीलंकाई सरकार जुलाई १९८७ के भारत-श्रीलंका समझौते में उल्लिखित प्रकार की वचनबद्धता नहीं कर पाती।

भारत-पाक संघर्ष

दक्षिण एशिया के 'असुरक्षा लक्षण' (यह शब्दावली स्टीफन पी. कोहन ने 'सिक्यूरिटी इश्यू इन साउथ एशिया' एशियन सर्वे, बर्कले, १९७५ में प्रयुक्त की थी) का मूल प्रश्न भारत और पाकिस्तान के बीच पारस्परिक संदेह है। जो कुछ भी कोहन द्वारा २५ वर्ष पहले लिखा गया था आज भी वैध

प्रतीत होता है। उन्होंने लिखा था, ''दक्षिण एशियाई सुरक्षा व्यवस्था एक असुरक्षा व्यवस्था है, और प्रत्येक क्षेत्रीय सरकार के लिए व्यापारिक सौदेबाजी में असुरक्षा की कमी अन्तर्ग्रस्त होती है न कि सुरक्षा में वृद्धि। असुरक्षा भले ही यह आन्तरिक अव्यवस्था अथवा बाहरी संघर्ष के कारण हो, आजादी के २५ वर्ष बाद मानदण्ड बन चुकी है और कोई भी ईमानदारी से नहीं कह सकता है कि इस स्थिति में प्रत्याशित भविष्य में सुधार के लिए पूर्णरूपेण परिवर्तन होगा। सैनिक लालफीताशाही वहाँ भी राजनीतिक व्यवस्था का अतिक्रमित संघटक बन चुकी है जहाँ उन्होंने अभी सत्ता नहीं सँभाली है; उनके अनेक असैनिक गठबन्धन हैं जो शक्तिशाली हैं और बाहरी शक्तियों ने स्थिति में सुधार के लिए थोड़ा परन्तु बेशकीमती कार्य किया है।'' यह समस्या जिसका राष्ट्रवादी आन्दोलन के दायरे में समाधान नहीं किया जा सका और जिसके कारण १९४७ में भारत का विभाजन हुआ, क्षेत्रा की स्थिरता के लिए एक ख़तरा बनी हुई है। क्षेत्रा के भीतर और बाहरी दखल ने इस मामले को और उलझा दिया है। भारत और पाकिस्तान ने तीन युद्ध लड़े हैं और सीमा पर कई टकराव हुए हैं। वर्तमान में वे कश्मीर के ऊपर शब्दों का युद्ध भी जारी रखे हुए हैं। भारत कश्मीरी लड़ाकों को पाकिस्तान के नैतिक और सामग्री समर्थन का अभियोग लगाता है जबकि पाकिस्तान भारत सरकार द्वारा कश्मीर में मानवाधिकार के हनन का अभियोग लगाता है।

मुख्य समस्या: अपेक्षित राजनीतिक विश्वास की कमी

ऊपर चर्चित समस्या का संचयी प्रभाव है दक्षेस को साहसी छलांग लगाने योग्य बनाने के लिए राजनीतिक विश्वास की कमी। यह संगठन 'द्विपक्षीय और विवादग्रस्त' मुद्दों से अलग रहकर स्वयं को सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण प्रश्नों जिन पर सम्बोधन की आवश्यकता है, पर विचार करने के अवसर से स्वयं को वंचित रखता है। एक-दूसरे पर विश्वास की यह कमी दूसरे क्षेत्रों में अपना प्रभाव छोड़ती है। उदाहरणार्थ, अन्तर्राज्यीय व्यापार आज भी बहुत छोटे स्तर पर है। भारत लगभग सभी दक्षिण एशियाई राष्ट्रों को औद्योगिक सामग्री और सेवाओं का एक सक्षम आपूर्त्तिकर्ता है परन्तु वे भारत की बजाए औद्योगिक पश्चिम, जापान और यहाँ तक कि चीन पर भी निर्भर रहने को प्राथमिकता देते हैं।

राजीव गाँधी के समय से ही भारत हमेशा एक दक्षिण एशियाई आम बाज़ार की जबर्दस्त वकालत करता रहा है। भारत में बड़ी संख्या में ऐसे संगठन और अकादमी संस्थाएँ हैं जो दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग और समेकन के कारणों की अविरल वकालत कर रहे हैं। इनमें जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और गुटनिरपेक्ष और अन्य विकासशील देशों के लिए अनुसंधान और सूचना तंत्रा शामिल हैं। इन्होंने बहुत ही गहन और उपयोगी अध्ययन किया है तथा असहयोग से होने वाले नुकसान का भी आकलन किया है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के महेन्द्र पी लामा द्वारा किए गए अध्ययन से पता चला है कि पाकिस्तान ने भारत और अन्य दक्षिण एशियाई देशों से चाय का आयात न करके १९९५-९७ के दौरान ११ करोड़ डालर से अधिक की हानि उठाई (''दक्षिण एशिया में चाय क्षेत्रा को समेकित करके : न्यू अपर्चुनिटीज़ इन ग्लोबल मार्केट'', साउथ एशियन सर्वे, दिल्ली जनवरी-जून २००१)। पाकिस्तान विश्व में चाय के विशालतम उपयोक्ताओं में से एक है। तथापि, यह चाय के अपने कुल १५ करोड़ किग्रा से अधिक का मुश्किल से १६ प्रतिशत दक्षिण एशिया से आयात करता है। इसका ६० प्रतिशत से अधिक चाय का आयात दूरस्थ केन्या से है जो कहीं अधिक लागत पर किया जाता है। यद्यपि ऐसा भारत के साथ कश्मीर समस्या है जो इस प्रकार के आयात प्रतिदर्श के पीछे मुख्य कारण है, यह वस्तुत: पाकिस्तान में स्थित बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के केन्या के चाय बागानों में व्यापक पैमाने पर स्वामित्व के कारण है।

संसाधन विकास की समस्या

एक अन्य क्षेत्रा जिसमें प्रगति नगण्य है, संसाधन विकास है। भारतीय उपमहाद्वीप में नदियों की व्यवस्था इस प्रकार है कि यदि इसे सम्पूर्ण क्षेत्रा को ध्यान में रखते हुए उचित रूप से प्रयोग किया जाए तो इससे विकास, सिंचाई, विद्युत निर्माण और पेयजल के संदर्भ में आश्चर्यजनक रूप से असर पड़ेगा। इसके अलावा यह यहाँ क्षेत्रीय चेतना राष्ट्रीय सुग्राह्यता का मार्ग प्रशस्त करती है। बी.जी.

वर्गीज की पुस्तक ''वाटर्स ऑफ होप (नई दिल्ली) : ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रैस, १९९०'' एक ऐसा दस्तावेज है जिससे पता चलता है कि इस सम्बन्ध में कितना कम किया गया है जबकि यहाँ बहुत कुछ किया जा सकता है। 'अन्ततः' वर्गीज लिखते हैं, ''सीमाओं से फर्क नहीं पड़ता बल्कि जनता से अवश्य पड़ता है, दक्षेस का दर्शन शायद सर्वाधिक सहयोगी प्रयास में प्रतिबिम्बित है जिससे गंगा-ब्रह्मपुत्रा-बारक जल की क्षमता को उपभोग में लाया जा सकता है। ये आशा के सागर हैं।''

२४.५ दक्षेस के लिए प्रत्याशाएँ

पार्थ घोष ने अपनी पुस्तक कोऑपरेशन एंड कनलिक्ट इन साउथ एशिया (१९८९) में इस दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया कि यद्यपि दक्षेस का सूत्रापात कर दिया गया था, ''राष्ट्रों के आन्तरिक विरोध संघों को क्षेत्राीय सहयोग का प्रभावी साधन बनाने के प्रति संघर्ष करेंगे।'' उन्होंने अनेक व्यापक क्रमबद्ध विविधताओं का उल्लेख किया और महसूस किया कि जब तक उन्हें दूर नहीं किया जाएगा, दक्षेस का भविष्य फीका रहेगा। इन विविधताओं का उपरोक्त के प्रति हवाला दिया गया है जैसे, शासन के स्वरूप, राष्ट्र-धर्म अन्तर्क्रियाएँ, भूमण्डलीय व्यवस्था के प्रति ढाँचागत गठजोड़, राष्ट्र-निर्माण रणनीतियाँ इत्यादि। स्थिति में अधिक परिवर्तन हुआ प्रतीत नहीं होता है। भारत-पाक रिश्तों के संदर्भ में इसकी स्थिति और बिगड़ गई है।

क्षेत्र के अन्तर्निहित सकारात्मक मुद्दे

ऐतिहासिक संदर्भ, स्थलाकृतिक और जनसांख्यिकीय लक्षणों, प्राकृतिक संसाधन अक्षयनिधियों और सामाजिक-सांस्कृतिक लोकाचार के होते हुए दक्षिण एशिया सहयोग और समेकन की सर्वाधिक प्राकृतिक यूनिट बन सकता है। इस क्षेत्रा के साथ कुछ ऐसे अन्तर्निहित मुद्दे है जिन्हें अवश्यमेव ध्यान में रखा जाना चाहिए। उदाहरणार्थ, क्षेत्राीय 'असुरक्षा संलक्षण' का संभवतया अधिकथन हुआ है। दक्षिण एशिया विश्व की न्यूनतम सैनिक शक्तिवाला क्षेत्रा है। यह क्षेत्रा जहाँ विश्व की २० प्रतिशत आबादी रहती है, विश्व के सैनिक व्यय के मात्रा एक प्रतिशत के लिए उत्तरदायी है। प्रतिस्पर्द्धात्मक आबादी वाले अन्य विकासशील क्षेत्रा (चीन को छोड़कर) भूमण्डलीय सैनिक व्यय का लगभग १५ प्रतिशत खर्च करते हैं।

यदि विकसित देशों से तुलना की जाए तो क्षेत्रा का रिकार्ड कहीं बेहतर है। विकसित विश्व जो यह घोषणा करने में गौरव मानता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उसकी मिट्टी पर कोई युद्ध नहीं हुआ है, भूमण्डलीय सैनिक व्यय का ८० प्रतिशत करते हैं और विश्व के शस्त्रा व्यापार के लिए ९७ प्रतिशत तथा भूमंडलीय सैनिक शोध एवं विकास के ९७ प्रतिशत के लिए उत्तरदायी हैं। दक्षिण एशिया का वित्तीय रक्षा भार क्षेत्रा के सकल राष्ट्रीय उत्पाद का लगभग ३ प्रतिशत है जो लैटिन अमेरिका के उल्लेखनीय निम्नतर १.२ प्रतिशत से अधिक है परन्तु अफ्रीका के ३.२ प्रतिशत और एशिया के १०.९ प्रतिशत से कम है। यह समग्र विकासशील विश्व के ४.३ प्रतिशत से भी कम है।

दक्षेस के भविष्य के बारे में आशावादी हुए बिना, यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि इस संगठन ने क्षेत्राीय नेताओं को कुछ नियमित अन्तराल पर बैठक करने का अवसर देकर एक राजनीतिक फोरम मुहैया कराया है जिसमें उनके मतभेद या तो निपटा दिए गए हैं अथवा समाप्त हो चुके हैं। जुलाई १९८७ के भारत-श्रीलंकाई समझौते का उद्‌गम नवम्बर १९८६ बंगलौर में हुई द्वितीय दक्षेस शिखर वार्त्ता के दौरान भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्राी राजीव गाँधी और श्रीलंका के राष्ट्रपति जूनियस जयवर्द्धने के बीच द्विपक्षीय वार्त्ता में निहित था। यह तर्क दिया गया कि दक्षेस के बिना भारत-पाक रिश्ते और अधिक बदतर हो गए होते।

अत्यधिक धीमी प्रगति के बावजूद, दक्षेस का एक उल्लेखनीय योगदान यह तथ्य रहा है कि यह शासकीय दक्षेस फोरम के बाहर सम्पूर्ण क्रियाकलापों पर काबू पाने में सक्षम रहा है। इस क्षेत्रा के आर-पार निजी क्षेत्रा में, ग़ैर-सरकारी संगठनों में इन क्रियाकलापों और सामुदायिक स्तर पर होने वाले क्रिया कलापों ने सभी प्रकार के राजनीतिक उतार-चढ़ाव देखे हैं। दक्षेस इतिहास कांग्रेस, दक्षेस

समाजशास्त्रीय कांग्रेस, शिशुविरोधी श्रम गठबंधन, व्यापारी फोरम, दक्षेस लेखक फोरम, मीडिया के लोगों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और पेशेवरों के जिनमें अभियन्ता, वास्तुकलाविद, सनदी लेखाकार शामिल हैं, के परिणामस्वरूप अन्तर-राज्यीय बौद्धिक पर्यटन में एक शाश्वत वृद्धि हो रही है। दक्षेस की बाबूगीरी के बिना भी यह प्रक्रिया जारी है। वस्तुत:, क्रियाकलापों की समान्तर प्रक्रिया ने शासकीय प्रक्रिया को अपनी पकड़ में ले लिया है और दोनों प्रक्रियाएँ बराबरी पर आ गई हैं। ये वे क्रियाकलाप है जिनसे दक्षेस भविष्य में अच्छा कार्यस्थल बनेगा और प्रक्रिया यथावत् रहेगी।

यह दक्षिण एशियाई कार्यों के प्रबन्धन में ग़ैर-राष्ट्र कर्मियों की उभरती हुई सजीव और निर्णायक भूमिका पर भी बल देता है। एक तरीके से, विश्वास निर्माण उपायों (सीबीएम) के सम्पूर्ण प्रतिदर्श जिसके बारे में हमने गत समय में दक्षिण एशिया में सम्बोधन किया था, का पुनर्मूल्यांकन, पुन: अभिकल्पित तथा पुनर्निर्माण करना है। अभी तक हम दक्षिण एशिया में सैनिक राजनीतिक विश्वास निर्माण उपायों पर गहन रूप से निर्भर रहे हैं। तथापि, गत ५० वर्षों में कोई भी राजनीतिक अथवा सैनिक विश्वास निर्माण उपाय कायम नहीं हुआ है। क्षेत्रा में शान्ति और सहयोग चुनाव क्षेत्रा हमेशा सीमान्त पर रखा गया है। विश्वास निर्माण उपायों केा अधिकांशत: केवल उनको बताया गया था जिन्होंने संघर्ष को कायम रखने के लिए गंभीर जोखिम उठाया है। सौभाग्यवश ये नकारात्मक जोखिम उठाने वाले हमेशा सूक्ष्म रूप से अल्पांश में रहे हैं।

इस प्रकार हमें भारत-पाकिस्तान संघर्षों के मामले में विशेष रूप से नए विश्वास निर्माण उपायों का निरूपण करने के बारे में विचार करना है। यह हमें आर्थिक विश्वास निर्माण उपायों – दक्षिण एशिया में विश्वास निर्माण उपाय और शान्ति स्थापना के उपाय के रूप में कारोबार तथा अन्य आर्थिक सहयोग (मार्ग III कूटनीति) के क्षेत्रा में ले जाता है। चूँकि संघर्ष को बनाए रखने में जोखिम उठाने वाले मौजूद हैं, शान्ति स्थापना के प्रति जोखिम उठाने वाले भी हैं। हमने कभी भी उत्तरवर्ती के प्रति स्वयमेव विचार नहीं किया है।

सतत आर्थिक सुधारों से उत्पन्न चुनौतियों ने प्रबल रूप से दक्षिण एशिया में राजनीतिक अर्थव्यवस्था को बदलना आरंभ कर दिया है। आर्थिक उदारीकरण राजनीतिक विशेषाधिकारों, अवरोधों को अधिकाधिक कमजोर करने के लिए अभिमुख हुआ है और शाब्दिक तौर पर दक्षिण एशिया को अन्तर्निहित शत्राुता वाली पुरानी सोच को बदलने के लिए मजबूर कर रहा है। क्षेत्राीय अवशेषों को आप्लावित करने वाले आन्तरिक संघ भेद का प्रभाव असहयोग की लागत में तीव्र वृद्धि से अधिक महत्त्वपूर्ण होता जा रहा है। लोकनीति के विशेष संदर्भ और रूपात्मकता ने जिनका होना न पारदर्शी था न उत्तरदायी, अधिक उदारता और दृढ़ता दिखाई है।

इस पृष्ठभूमि के विरुद्ध, प्रमुख बड़े मुद्दे जैसे सम्पूर्ण क्षेत्रा में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन से आर्थिक सुधारों का तालमेल, प्राकृतिक संसाधन, प्रौद्योगिकी और प्रबंधन पर विशिष्ट रुझान के साथ बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की भागीदारी के आधार को विस्तृत करना तथा अन्त: प्रवर्धी और बाह्य आघातों को झेलने के लिए योग्यता एवं क्षमता तथा सामूहिक पुनरुत्थान के प्रति आगे बढ़ना तीन मूलभूत चुनौतियाँ हैं। दक्षेस सहयोगियों की अवशोषी और युक्तिचालन क्षमता प्रत्येक क्षेत्रा के अभिगमों और उनके समेकन द्वारा व्यापक रूप से अवधारित की जाएगी। आई. पी. ए. इस क्षेत्रा में बहुमुखी विकास को भलीभाँति प्रवर्त्तित कर सकता है और इसीलिए सम्पूर्ण क्षेत्रा की क्षमताएँ इसके रणनीतिक उद्देश्य के प्रति गतिशील की जानी चाहिए।

दक्षिण एशियाई आर्थिक संघ

माले में १९९७ में आयोजित नौवीं दक्षेस शिखर वार्त्ता में दो क्षेत्राीय उच्चस्तरीय समितियों के प्रतिष्ठान को नामत: स्वतंत्रा विशेष ग्रुप को समेकित कार्रवाई योजना के कार्यचालन की जाँच करने तथा प्रतिष्ठित व्यक्तियों के ग्रुप को प्रमुखत: एक व्यापक दर्शन विकसित करने, संदर्श कार्रवाई योजना जिसमें वर्ष २००० और उसके आगे के लिए कार्यसूची शामिल हो, को तैयार करने तथा उन लक्ष्यों जिन्हें वर्ष २००० तक प्राप्त किया जा सकता है और प्राप्त किया जाना चाहिए, का विश्लेषण करने के लिए निर्देश दिया गया। स्वतंत्रा विशेषज्ञ ग्रुप (IEG) ने दक्षेस के सम्पूर्ण कार्यक्रम का बड़े पैमाने

पर पुनरीक्षण और पुनर्निर्माण करने की संस्तुति की। परिणामस्वरूप, एस. आई. पी. ए. के अधीन क्रियाकलापों के क्षेत्रा मूल ग्यारह से घटकर पाँच रह गए जिनमें ऊर्जा और पर्यावरण भी शामिल थे। दूसरी तरफ, प्रतिष्ठित व्यक्तियों के ग्रुप ने एक बहुत व्यापक और सुस्पष्ट सड़क मार्ग का नक्शा मुहैया कराया। प्रतिष्ठित व्यक्तियों के ग्रुप ने सिफारिश की कि क्षेत्रीय आर्थिक एकता आवश्यक है और समयबद्ध योजना का सुझाव दिया जिसमें वर्ष १९९९ तक ऐसी दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्रा संधि पर बातचीत करना शामिल है जिसका उसके तुरंत बाद कार्यान्वयन तथा दक्षेस सदस्यों के लिए यह २००८ तक तथा दक्षेस लिपिक वर्ग के लिए २०१० तक बढ़ाया जाए।

यह २०१५ तक दक्षेस सीमा शुल्क संघ तथा २०२० तक दक्षेस आर्थिक संघ का भी निर्धारण करता है। इसमें सामाजिक रणक्षेत्रा में दूरगामी सिफारिशें भी की गईं जो ग़रीबी उन्मूलन, महिलाओं के सशक्तीकरण और महिलाओं और बच्चों के अवैध व्यापार पर हैं।

इस्लामाबाद में आयोजित बारहवीं दक्षिण शिखर वार्त्ता में भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय सम्बन्धों में उल्लेखनीय सुधार की भी चर्चा की गई। इसमें दक्षिण एशियाई आर्थिक संघ के गठन के लिए काठमाण्डु में ग्यारहवीं शिखर वार्त्ता में की गई वचनबद्धता को दुहराया गया। तदनुसार, शिखर वार्त्ता में समेकन प्रक्रिया के प्रथम चरण की ओर बढ़ने अर्थात् २००६ तक दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्रा के प्रचालन का निर्णय किया गया।

बोध प्रश्न ३

नोट : i) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए रिक्त स्थान का प्रयोग करें।

ii) अपने उत्तर इकाई-अंत में दिए गए उत्तरों से मिलाएँ।

१) ऐसी कौन सी समस्याएँ हैं जो दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग के मजबूत करने के रास्ते में आड़े आई हैं?

.....

.....

.....

.....

.....

२) कौन-से घटक भविष्य में दक्षेस के लिए शुभ शकुन प्रकट करते हैं?

.....

.....

.....

.....

.....

२४.६ सारांश

दक्षेस (दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ) दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग की प्रथम प्रमुख सजीव अभिव्यक्ति है। इसमें सात राष्ट्र शामिल हैं – बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। १९८५ से आरंभ होकर अब तक ग्यारह दक्षेस शिखर वार्ताएँ हो चुकी हैं। नामत:

ढाका, बंगलौर, इस्लामाबाद, माले, कोलम्बो, ढाका, नई दिल्ली, माले, कोलम्बो और काठमाण्डु; बारहवीं इस्लामाबाद में होनी है। यह संगठन कतिपय अन्तर्निहित विरोधों, विरोधाभासी सुरक्षा संदर्श, विविध राजनीतिक संस्कृतियों और अपेक्षित राजनीतिक संकल्प की कमी के कारण समस्याओं को झेल रहा है। भारत की प्रबल स्थिति भी एक समस्या है। तथापि, इस क्षेत्रा में कतिपय अन्तर्निहित सकारात्मक मुद्दे हैं जो दक्षेस देशों द्वारा बेहतर कल के निर्माण को आशाजनक रूप से सहज बनाएँगे।

२४.७ कुछ उपयोगी पुस्तकें

अगवानी, एम.एस., (संपादकीय) १९८३, *साउथ एशिया: स्टेबिलिटी एण्ड रीज़नल कोऑपरेशन* (चण्डीगढ़: सीआरआरआईडी)।

घोष, पार्थ, एस., १९८९, *कोऑपरेशन एण्ड कान्लिक्ट इन साउथ एशिया,* नई दिल्ली।

गोनसाल्वेस, ऐरिक एण्ड नेन्सी जेटली, १९९९, *दि डायनामिक्स ऑफ साउथ एशिया: रीजनल कोऑपरेशन एण्ड सार्क,* सेज।

लामा, महेन्द्र पी, (संपादकीय), १९९०, *इकोनॉमिक कोऑपरेशन इन द सार्क रीजन: पोटेन्शियल, कान्स्ट्रेन्ट्स एण्ड पोलिटिक्स,* इण्टरेस्ट पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली।

लामा, महेन्द्र पी, (सं.), २००१, *साउथ एशियन ग्रोथ क्वाड्रेंगल: एमरजिंग ऑपर्च्यूनिटीज़ फॉर इकोनोमिक पार्टनरशिप,* फिक्की, नई दिल्ली।

मुनि एस.डी., एण्ड अनुराधा मुनि, १९८४, *रीज़नल कोऑपरेशन इन साउथ एशिया,*नई दिल्ली।

सेन गुप्ता, भवानी, १९८८, *साउथ एशियन परस्पेक्टिव्स: सेवन नेशन्स इन कान्लिक्ट एण्ड कोऑपरेशन,* दिल्ली।

गुट निरपेक्ष और विकासशील देशों के लिए शोध एवं सूचना तंत्रा (रिसर्च एण्ड इनफोरमेशन सिस्टम फॉर द नन-एलाइण्ड एण्ड डपलॅपिंग कण्ट्रीज़), २००४ *साउथ एशिया: डवलॅपमेण्ट कोऑपरेशन रिपोर्ट २००३/०४,* नई दिल्ली।

साण्ड, रिक, (सं.), *इकोनॉमिक लिबरलाइज़ेशन इन साउथ एशिया,* मेकमिलन, दिल्ली।

२४.८ बोध प्रश्नों के उत्तर

बोध प्रश्न १

१) आपके उत्तर में निम्न मुद्दे होंगे: १९४७ से क्षेत्रीय संगठन बनाए जाने के लिए सतत प्रयास, उत्तर-दक्षिण वार्तालाप की विफलता, तेल मूल्यों में वृद्धि, क्षेत्रा के नेताओं की बोधगम्यता में परिवर्तन।

२) दक्षेस की चार-चरण वाली संरचना के शीर्ष पर राष्ट्राध्यक्षों की वार्षिक शिखर वार्ता है। इसके नीचे विदेश मंत्रियों का सम्मेलन, विदेश सचिवों की स्थायी समिति और विशेषज्ञों तथा कर्मचारियों की तकनीकी समितियाँ हैं।

बोध प्रश्न २

१) शिखर वार्ता ने अपनी प्रस्तावना में ''बलों का प्रयोग नहीं'' और ''सभी विवादों का शान्तिपूर्ण समाधान'' शब्दावलियों को यथास्थिति रखा है।

बोध प्रश्न ३

१) सदस्य राष्ट्रों की विविध राजनीतिक संस्कृतियाँ, सामान्यत: विरोधाभासी सुरक्षा संदर्श और विशेषतया भारत-पाकिस्तान संघर्ष, राजनीतिक दबाव की कमी आदि।

२) दक्षेस की महान् प्रत्याशाएँ हैं: क्षेत्रा न्यूनतम सैनिक सम्पन्न रहे; क्षेत्रा का एक सर्वनिष्ठ इतिहास और संस्कृति हो; मध्यम वर्ग का कुल मिलाकर, समान दृष्टिकोण हो।